(2007) 9 SCR 1011

बृजभूषण यादव और अन्य

बनाम

भारतसंघ और अन्य

सितंबर 14, 2007

(तरुण चटर्जी और पी. सदाशिवम, जे. जे.)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947:

धारा25. कामगारों का दावा कि एजेंसी के माध्यम से उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद उन्हें सीधे विभाग द्वारा नियुक्त किया गया था. श्रम न्यायालय ने दावा स्वीकार कर लिया और निष्कासन के आदेश को रद्द कर दिया- उच्च न्यायालय ने श्रम न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया. उच्चतम न्यायालय के समक्ष, विभाग ने इस स्थिति का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति मांगी किस भी श्रमिकों को एजेंसी द्वारा नियुक्त किया गया था न कि विभाग द्वारा. उक्त पहलू के संदर्भ में नए सिरे से निपटान के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया मामला।

अपीलार्थियों. कर्मचारियों का मामला यह था कि उन्हें एक एजेंसी के माध्यम से सुरक्षागार्ड के रूप में 1.10.1996 को नियुक्त किया गया था और

अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद 1.10.1997 तक, संबंधित श्रमिकों को काम प्रदान किया गया था। दूरसंचार विभाग 31.5.1999 तक, और उसके बाद इस विभाग और श्रमिकों के बीच सीधे मालिक और नौकर संबंध था और चूंकि श्रमिकों ने 240 दिनों से अधिक समय तक सुरक्षागार्ड की निरंतर सेवा प्रदान की थी, इसलिए उनकी बर्खास्तगी गलत थी।

श्रम न्यायालय ने श्रमिकों के मामले को स्वीकार कर लिया और पूर्ण वेतन के साथ बहाली का आदेश दिया।उच्च न्यायालय ने विभाग के दावे पर निर्भर करते हुए कहा कि सुरक्षा एजेंसी के साथ अनुबंध समय-समय पर 31.5.1999 तक बढ़ाया गया था और यह पाया गया कि कर्मचारी दूरसंचार के कर्मचारी नहीं थे, और अधिकरण के फैसले को रद्द कर दिया।

इस न्यायालय में अपील में, श्रमिकों ने तर्क दिया कि अनुबंध समाप्ति के बाद अर्थात 1.11.1997 से हालांकि दूरसंचार विभाग द्वारा 31.5.1999 तक श्रमिकों को नियुक्त किया गया था, उच्च न्यायालय को श्रम न्यायालय द्वारा लाए गए तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

अपील का निपटारा करते हुए और मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषित करते हुए, न्यायालय - निर्णित: उच्च न्यायालय के आदेश के अवलोकन से यह नहीं पता चलता है कि सुरक्षा एजेंसी के साथ अपने अनुबंध को 31.05.1999 तक बढ़ाने के आदेश /आदेशों के लिए कोई विशिष्ट संदर्भ और चर्चा की गई थी। वास्तव में, इस न्यायालय के समक्ष, उत्तरदाता

विभाग ने अपने इस रुख के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया है कि किसी भी श्रमिक सुरक्षा एजेंसी द्वारा नियुक्त किया गया था न कि विभाग द्वारा।चूंकि सुरक्षा एजेंसी के साथ समझौता या अनुबंध संदर्भ में उठाए गए मुद्दे पर विचार करने के लिए प्रासंगिक सामग्री है और उच्च न्यायालय द्वारा किसी विशिष्ट चर्चा और निष्कर्ष के अभाव में, उक्त पहलू के संदर्भ में मामले को नए सिरे से निपटाने के लिए उच्च न्यायालय को भेज कर न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा।

विभाग के साथ-साथ श्रमिक दोनों को अपने-अपने दावे के समर्थन में उच्च न्यायालय के समक्ष सभी प्रासंगिक सामग्री रखने की अनुमति है और यह उच्च न्यायालय को गुण-दोष के आधार पर इस मुद्दे पर निर्णय लेना है। (पैरा 12, 13 और 14, 1015.सी.जी)

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4264/2007

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 08.08.2005 दिनांकित निर्णय और आदेश में न्यायिक प्रक्रिया C.M.W.P. सं. 22316,22318.22323,22325, 22327, 22328 , 22332 , 22334 , 23517 , 23521 , 23522 , 23525 , 23526 , 23533 और 2003 का 23538।

अपीलार्थीगण की ओर से अमित कुमार।

आर. डी. अग्रवाल, पवनकुमारऔरसुमितकुमार ठाकुर - उत्तरदाताओं की ओर से।

जी. प्रकाश और वी. के. वर्मा - भारत संघ की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

पी. सदाशिवम, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. वे कर्मचारी, जिन्होंने केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण. सह. श्रम न्यायालय, लखनऊ; संक्षेप में "अधिकरण सह. श्रम न्यायालय" की पूर्ण पीठ द्वारा बहाली और वेतन के लिए पंचाट प्राप्त किया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष उस पंचाट को खो दिया गया, इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता हैं।

3. उपरोक्त अपील दिनांकित 08.08.2005 आदेश के खिलाफ निर्देशित है। जिसके द्वारा इलाहाबाद में उच्च न्यायालय ने भारत संघ दूरसंचार मंत्रालय, भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिकाओं के समूह को अनुमति दी और अधिकरण सह श्रम न्यायालय द्वारा पारित पंचाट को रद्द कर दिया।

4. हालाँकि अधिकरण सह. श्रम न्यायालय ने एक अलग लेकिन समान आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि संबंधित श्रमिकों की सेवाओं

की समाप्ति अवैध थी।भारतसंघ और भारत संचार निगम लिमिटेड ने अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर करके उच्च न्यायालय के समक्ष पूर्ण वेतन के साथ बहाली का आदेश को चुनौती दी।

5. उच्च न्यायालय ने आई. डी. सं. 39/2001 में तथ्यों को स्वीकार करते हुए, अर्थात् श्री बृज भूषण यादव बनाम महाप्रबंधक, दूरसंचार विभाग ने विभाग के रुख को स्वीकार किया और उसमें दिए गए पंचाट को रद्द कर दिया। इसी तरह के आदेश अन्य सभी संबंधित रिट याचिकाओं में भी पारित किए गए हैं।

6. हमने अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री अमित कुमार और उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर. डी. अग्रवाल को सुना।

7. इसके तहत पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, हमारा विचार है कि पक्षों द्वारा बताए गए सभी तथ्यात्मक मैट्रिक्स को संदर्भित करना अनावश्यक है। उस पर कामगार द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर, केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खंड (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री बृज भूषण यादव और महाप्रबंधक, दूर संचार विभाग, वाराणसी के बीच औद्योगिक विवाद को निर्णय के लिए भेजा। न्यायनिर्णयन के लिए संदर्भित संदर्भ निम्न प्रकार हैः

"क्या दूरसंचार विभाग के प्रबंधन की कार्रवाई श्री बृजभूषण यादव की WEF 1.6.1999 से सेवाओं को समाप्त करना उचित है? यदि नहीं, तो कामगार किस राहत का हकदार है?"

कर्मचारी के अनुसार, उन्हें शुरू में दूरसंचार विभाग, वाराणसी (पूर्व), वाराणसी डब्ल्यू. ई. एफ. 1.10.1996 के साथ सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था और वे तब तक अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे जब तक कि उनकी सेवाओं को डब्ल्यू. ई. एफ. 1.6.1999 समाप्त नहीं कर दिया गया।सुरक्षा गार्डों को नियुक्त करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ कोई वास्तविक अनुबंध श्रम प्रणाली प्रचलित नहीं थी।तथाकथित सुरक्षा एजेंसी अर्थात मेसर्स सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन सर्विसेज केवल एक नाम का ऋणदाता था और श्रम की खरीद के लिए दूरसंचार विभाग का लगभग एक दलाल या एजेंट था और एक पंजीकृत लाइसेंसधारी ठेकेदार नहीं था। उन्होंने अपनी समाप्ति से पहले बारह कैलेंडर महीनों में 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया।बिना नोटिस या छंटनी, मुआवजे के उनकी बर्खास्तगी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25.एफ के प्रावधानों के विपरीत है और वह पिछले वेतन के साथ बहाली का हकदार है।

8. नियोक्ता दूरसंचार विभाग के अनुसार, उनकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षागार्ड की अस्थायी आवश्यकता थी, इसलिए, एक मैसर्स

सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन सर्विसेज, वाराणसी और महाप्रबंधक (पूर्व), वाराणसी के बीच 10.9.1996 पर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।अनुबंध की शर्तों के तहत, कर्मचारी को उक्त सुरक्षा सेवाओं द्वारा सुरक्षागार्ड का काम करने के लिए आपूर्ति की गई थी और वह 1.10.1996 के बाद से सुरक्षागार्ड के कर्तव्यों का पालन कर रहा था।दूरसंचार विभाग की वस्तुओं और उपकरणों की सुरक्षा के लिए, दूरसंचार विभाग ने पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर मेसर्स सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन सर्विसेज के साथ एक अनुबंध किया था। इसे श्रम आयुक्त द्वारा विधिवत पंजीकृत किया गया था। अनुबंध निश्चित अवधि के लिए था, जिसकी अवधि समाप्त हो गई। कर्मचारी को दूरसंचार विभाग के कर्मचारी के रूप में नहीं लिया गया था और न ही उसने 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था और इसलिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25.एफ के तहत प्रदान किया गया नोटिस या छंटनी मुआवजा लागू नहीं होता है।

9. अधिकरण सह. श्रम न्यायालय ने सामग्री पर विचार करने के बाद कहा कि करार की समाप्ति के बाद से यानी 31.10.1997 पर, श्री बृजभूषण यादव सहित सभी कामगारों को दूरसंचार विभाग 31.05.1999 तक, उक्त अवधि के दौरान विभाग और कर्मचारी के बीच सीधे स्वामी और सेवक संबंध थे और उन्होंने देखा कि कर्मचारी ने सीधे विभाग के तहत 570 दिनों के लिए सुरक्षागार्ड की निरंतर सेवा प्रदान की जो 240 दिनों से अधिक है और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25.बी के तहत परिभाषित

"निरंतर सेवा" की परिभाषा के अंतर्गत आता है।अधिकरण सह. श्रम न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25.एफ के प्रावधानों के लाभों को लागू करके कामगार के मामले को स्वीकार कर लिया और पूर्ण वेतन के साथ बहाली प्रदान करते हुए पंचाट पारित कर दिया। अन्य लोगों के संबंध में भी इसी तरह के पंचाट जारी किए गए हैं।

10. भारतसंघ और बी. एस. एन. एल. द्वारा दायर रिट याचिकाओं में, उच्च न्यायालय ने न्यायालय ने मुख्य रूप से विभाग के इस दावे पर भरोसा करते हुए कि सुरक्षा एजेंसी. मेसर्स सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन सर्विसेज, वाराणसी के साथ अनुबंध कोसमय-समय पर 31.5.1999 तक बढ़ाया गया था और यह पाते हुए कि संबंधित कर्मचारी दूरसंचार विभाग के कर्मचारी नहीं थे, अधिकरण के फैसले को रद्द कर दिया।

11. हमारे सामने, कामगार की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, जोरदार तरीके से उन्होंने तर्क दिया कि समझौते की समाप्ति के बाद यानी 1.11.1997 से, हालांकि दूरसंचार विभाग द्वारा 31.5.1999 तक श्रमिकों को नियुक्त किया गया था, उच्च न्यायालय को दूरसंचार विभाग द्वारा प्राप्त तथ्य के निष्कर्ष में अधिकरण सह.श्रम न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, दूसरी ओर, विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने यह इंगित करते हुए कि सुरक्षा एजेंसी के साथ, अनुबंध को 31.5.1999 तक बढ़ाया गया था। उच्च न्यायालय विभाग के इस रुख को स्वीकार

करने में सही था कि ये कर्मचारी विभाग के कर्मचारी नहीं थे, इसलिए, हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

12. हमने प्रासंगिक सामग्रियों और प्रतिद्वंद्वियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।यद्यपि उच्च न्यायालय ने विभिन्न तथ्यात्मक पहलुओं केसाथ-साथ इस न्यायालय के निर्णयों को इंगित करते हुए एक लंबा आदेश पारित किया, जैसाकि सही बताया गया है, सुरक्षा एजेंसी के साथ विभाग द्वारा अनुबंध को 31.05.1999 तक बढ़ाने के लिए विभिन्न आदेशों को उच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से उजागर नहीं किया गया है।यदि यह स्थापित किया जाता है कि 30.10.1997 के बाद, वहाँ यदि सुरक्षा एजेंसी और विभाग के बीच कोई वैध अनुबंध नहीं था, तो कर्मचारियों के इस रुख को स्वीकार किया जाना चाहिए कि उन्हें दूरसंचार विभाग द्वारा सुरक्षागार्ड के रूप में जारी रखा गया था। जैसाकि पहले देखा गया है, उच्च न्यायालय के आदेश के अवलोकन से यह नहीं पता चलता है कि कोई विशिष्ट संदर्भ और सुरक्षा एजेंसी के साथ अपने अनुबंध को 31.05.1999 तक बढ़ाने के आदेश /आदेशों पर चर्चा की गई।

13. वास्तव में, इस न्यायालय के समक्ष, उत्तरदाता विभाग ने एक याचिका दायर की है, उनके इस रुख के समर्थन में कि सभी श्रमिकों को सुरक्षा एजेंसी द्वारा नियोजित किया गया था, विभाग द्वारा नहीं, अनुबंध आर.3 से आर.8 के रूप में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति

के लिए आवेदन।चूंकि सुरक्षा एजेंसी के साथ समझौता या अनुबंध संदर्भ में उठाए गए मुद्दे पर विचार करने के लिए प्रासंगिक सामग्री है और उच्च न्यायालय द्वारा किसी विशिष्ट चर्चा और निष्कर्ष के अभाव में, हमारा विचार है कि उक्त पहलू के संदर्भ में मामले को नए सिरे से निपटाने के लिए उच्च न्यायालय को भेजकर न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा।हालाँकि हमने दोनों पक्षों के कुछ तथ्यात्मक विवरणों को स्वीकार किया है, लेकिन यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

14. ऊपर जो कहा गया है, उसके आलोक में हम विवादित आदेश को अलग करते हैं।इन सभी मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया और निर्वाह के बारे में एक विशिष्ट निष्कर्ष प्रस्तुत करने के बाद नए सिरे से निपटान के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया। 31.05.1999 तक सुरक्षा एजेंसी के साथ समझौते या अनुबंध का अस्तित्व और उचित आदेश पारित करना।विभाग के साथ-साथ श्रमिकों दोनों को अपने-अपने दावे के समर्थन में उच्च न्यायालय के समक्ष सभी प्रासंगिक सामग्री रखने की अनुमति है और यह उच्च न्यायालय पर है कि वह इस मुद्दे पर गुण-दोष के आधार पर जल्द से जल्द निर्णय ले।

15. अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों पर किया जाता है।कोई लागत नहीं।

डी जी अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुरेश कुमार सेन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।